

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-02/2024-4273

व०प०, राँची, दिनांक-01/11/24

प्रेषक,

जलज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय,
हरमू चौक, राँची-834002.

E-mail के माध्यम से
परिवेश पोर्टल पर
upload करने हेतु

विषय :- मेसर्स आलोक इण्डस्ट्रीज के मिनी प्लांट हेतु 9.27 हे० वनभूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-FP/JH/ENCRH/39652/2019/436 दिनांक-11.07.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत परियोजना में की गई पृच्छा का प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-872 दिनांक-23.09.2024 से प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन


30/10/2024

(जलज कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-वन भूमि-02/2024-4273

व०प०, राँची, दिनांक-01/11/24

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

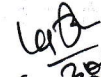

30/10/2024

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-वन भूमि-02/2024-4273

व०प०, राँची, दिनांक-01/11/24

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/Technical Head, Alope Steel Industries Pvt. Opp. Ashok Cinema, Ranchi Road, Marar, Dist-Ramgarh-829117 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


30/10/2024

विशेष कार्य पदाधिकारी।

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भूमे, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email-pecf-ednodal@gov.in

पत्रांक:- 872

दिनांक:- 23/9/2024

सेवा में,

सचिव,

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय

मेसर्स आलोक इण्डस्ट्रीज के मिनी प्लांट हेतु 9.27 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव सं० FP/JH/ENCRH/39652/2019 के संबंध में।

प्रसंग :-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय राँची के पत्रांक FP/JH/ENCRH/39652/2019/436 दिनांक 11.07.2024

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव सं० FP/JH/ENCRH/39652/2019 हेतु कुल 9.27 हे० वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर कुल 02 बिन्दुओं पर पृच्छा की गयी है।

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय राँची द्वारा की गयी पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 1741 दिनांक 12.09.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय में समर्पित की गयी है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के प्रतिवेदनानुसार भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय राँची द्वारा की गयी पृच्छा का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत् है:-

क्र०सं०	पृच्छाए	निराकरण
1	During site inspection no information was provided towards actions taken towards the forest land encroachment. Therefore, if Revenue department or Forest department of state has taken any action against the contextual forest land encroachment, the same should be informed to this office.	The applied area involves regularization of 7.00 ha of Jungle-Jhari land, where forest department has not taken any action as the said land is beyond its jurisdiction. The revenue authorities (Deputy Commissioner, Ramgarh) was requested for response over the matter, which he has done (Anx-A). In the response it is clear that revenue authorities didn't take action as the said land was already settled as per existing records and the same land was bought by Alok Industries Ltd. Once it came to their notice that the nature of land is Jungle Jhaari and even settled Jungle Jhaari will need forest clearance, the charge for the same land parcel was instructed to be deposited before issuing of NOC and the User Agency has also deposited 80% of the amount in Nov 2022. Meanwhile, the process of cancellation of old jamabandi has also started. Thus, this case may be considered for regularization considering the special nature of the case in hand, and non-deliberate non-compliance.
2	It was informed to inspecting team that permission to use surface water for the plant has been given by Damodar Valley Corporation (DVC). The State Government may like to clarify it DVC is competent to grant such permission.	Reply of U/A:- "M/s ASIPL obtained permission for water drawl from Damodar River. It is issued by Central Water Commission (CWC), Damodar Valley River Regulation Committee (DVRRC) Unit, Govt. of India vide letter no. MD/DVRR/W-6/2006/450-456 dated. 07.08.2006 for 6.37 MGD. Further wate quantity is reduced to 0.644 MGD water vide letter dated 09.08.2016, copies of the letters are enclosed as Annexure-I.

सांचव कौषांग

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

सं० 5072

25 SEP 2024

झारखण्ड, राँची

4/जनगडुम/2024
5908
25/9/2024

		"Damodar Valley" under the Damodar Corporation Act, 1948 as defined in Clause Section 2. This is an act for the establishment regulation for the development of the Damodar Valley in the provinces of Bihar (now Jharkhand) and West Bengal. The constitution of the corporation defined in Clause (1)(d) of section 4 of the Act, the Government of Jharkhand and West Bengal are the members in constituted body of the corporation In the said Act section 12 denotes the functions of the corporation Water supply is one of the functions denoted in Clause (a) of section 12 of the Act. The concurrence for drawing of water issued vide letter dated 07.08.2006 by the Member Secretary, DVRR, Govt. of India, Central Water Commission, DVRR Unit, Maithan Dam, Dhanbad in the light of resolution taken under item 113.2.15.1 during the 113th meeting of DVRR Committee held at Kolkata on 14.06.2006. The water allocation from Damodar River is issued by the Central Water Commission, Damodar Valley River Regulation Committee, Govt. of India under the provision of Law as detailed above. As per Clause -G of the letter dated 07.08.2006 (Annexure-I) the agreement is to be executed with DVC and charges of water drawl to be paid to DVC accordingly DVC acted upon and charges of water are being paid by ASIPL, latest bill of water and its payment enclosed as Annexure-II" Comments of DFO:- "The legal position has been stated by UA and the permission (Anx-I and Anx-II) is valid."
--	--	---

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, ब्रोकरो से प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन इस पत्र के साथ सलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना प्रस्ताव हेतु कुल 9.27 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज-I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:-यथोक्त।

अनुपालन प्रतिवेदन तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

K. Dr.

23.9.24